कोविड–19 योद्धाओं को सलाम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 30 जनवरी, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य एमरजेंसी की घोषणा की, जिसका आधार यह बताया गया कि दिसम्बर, 2019 से अनजान कारणों से होने वाला न्यूमोनिया रोग फैल चुका था। इसके बाद इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस (आईसीटीवी) ने 11 फरवरी, 2020 को नए विषाणु के नाम के रूप में "सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (सार्स–सीओवी–2)" की घोषणा की। इस नाम का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यह विषाणु आनुवंशिक तौर पर कोरोना वायरस से संबंधित है, जोकि 2003 में सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) के लिए जिम्मेदार था। डब्ल्यूएचओ ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा पूर्व में निर्धारित दिशा–निर्देशों के आधार पर 11 फरवरी, 2020 को इस नए रोग का नाम कोविड–19 घोषित किया।

तदोपरांत, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड–19 को एक महामारी पैंडेमिक (महामारी पैंडेमिक नई बीमारी का विश्वव्यापी फैलाव है) के रूप में घोषित किया और सभी देशों से प्रबलता से अपील की कि इस रोग की पहचान, इसके इलाज और इसके फैलाव को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कोविड–19 के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 25 मार्च, 2020 की अर्द्धरात्रि से देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की, जिसकी अवधि बढ़ाकर बाद में 31 मई, 2020 तक कर दी। भारत सरकार वे सभी अपेक्षित उपाय कर रही है जिससे यह सुनिश्चित हो कि भारत तेजी से फैलती कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न् चुनौतियों का भली–भांति सामना करने के लिए तैयार हो सके।

इस कठिन समय में कोविड–19 कर्मयोद्धा, जिनमें डॉक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी, डाकघर, बैंक कर्मी तथा जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाले अन्य सरकारी कार्मिक शामिल हैं, लोगों की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

स्वास्थ्य कार्मिक, जिनमें डॉक्टर और नर्सें शामिल हैं, कोविड–19 के फैलाव को नियंत्रित करने की दिशा में ये कार्मिक बचाव से लेकर निदान तथा इलाज से लेकर देखभाल तक सभी कार्यों में फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में ये लोग संक्रमण का जोखिम उठाकर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संक्रमण के खतरे के साथ–साथ ये स्वास्थ्य कर्मी लंबी अवधि तक कार्य करने, मनोवैज्ञानिक दबाव, परिश्रम भरे कार्य के कारण अत्यंत थकान आदि का भी सामना कर रहे हैं। हालांकि, इन सभी कठिनाईयों का सामना करते हुए भी देशभर के ये स्वास्थ्य कर्मी, कोविड–19 से इस जंग में शानदार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का https://covidwarriors.gov.in पर ऑनलाइन डाटापूल तैयार किया है। इस प्रयास के भाग के रूप में, देशभर के लगभग 11 लाख चिकित्सकों और 17 लाख नर्सों की सूची तैयार की गई है, जिनकी सेवाओं का इस्तेमाल राज्य, जिला तथा नगरपालिका द्वारा जमीनी स्तर पर कोविड–19 के विरूद्ध इस युद्ध में किया जा रहा है।

पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्मिक भी कोविड–19 के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं कार्मिकों की बदौलत यह संभव हो पा रहा है कि सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन हो और लॉकडाउन कड़ाई से लागू हो, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और यह भी कि आपराधिक तत्व किसी भी प्रकार से इस महामारी के फैलाव का लाभ उठाकर कोई वारदात न कर सकें। पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़े यही कार्मिक, सील किए हुए क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) की पहरेदारी के साथ–साथ लॉकडाउन एवं घर पर क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और साथ ही, अत्यधिक जोखिमवाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल रहे हैं।

इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ–साथ लगभग 5 मिलियन (50 लाख) ऐसे सफाई कार्मिक भी है, जो रोजाना अपनी जान को जोखिम में डाल कर हमारे गली–मोहल्लों, पार्कों, सीवरों, सेप्टिक टैंकों, सामुदायिक स्थलों, सार्वजनिक शौचालयों तथा अन्य जगहों पर साफ–सफाई सुनिश्चित कर कोविड–19 के फैलाव को काबू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इन हालात में, डाकघरों और बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इस नाते इन्हें कोविड–19 के लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट प्रदान की गई है। विभिन्न बैंक, मोबाइल एटीएम की सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ लोगों को नकदी जमा तथा आहरण, चेक क्लीयरेंस (निकासी), धन प्रेषण तथा सरकारी लेन–देन जैसी सहूलियतें और एमएसएमई ग्राहकों तथा कृषि और स्वयंसेवी समूहों जैसे वर्गों के लिए अतिरिक्त लिक्विडिटी जैसी स्कीमों की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। डाक विभाग, विश्व की विशालतम डाक सेवा का संचालन करता है और विभाग, अपने सुदृढ़ और व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जीवनरक्षक दवाओं से लेकर कोविड–19 जांच किट, एन 95 मास्क, वेंटिलेटर तथा अन्य जरूरी चिकित्सकीय उपस्कर मुहैया करा रहा है। इसके अतिरिक्त, 8 जुलाई, 2020 तक, डाक विभाग के कार्मियों ने डाकघर बचत बैंक खातों में कुल 2.59 लाख करोड़ रु. मूल्य के 13 करोड़ से अधिक लेन–देन कार्य, आईपीपीबी के जरिए 13,000 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के 5.36 करोड़ लेन–देन कार्य तथा आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के जरिए 3,249 करोड़ रु. मूल्य के 1. 63 करोड़ लेन–देन कार्यों को सुलभ कराना सुनिश्चित किया।

सरकार ने कोविड–19 महामारी के चलते विभिन्नो देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश लाने के उद्देश्य से वंदे भारत मिशन योजना शुरु की है, जिसके कारणवश विदेशों में मौजूद भारतीयों के साथ–साथ यहां भारत में उनके निकट संबंधियों को भी काफी राहत मिली है। यह मिशन 7 मई, 2020 को आरंभ हुआ। इसकी शुरुआती उड़ानें अबू–धाबी और दुबई से क्रमशः कोच्चि तथा कोझिकोड़ पहुंची। इसी प्रकार, विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों तथा अन्य लोगों को उनके गंतव्य स्थ्लों तक पहुंचाने के संबंध में गृह मंत्रालय का संगत आदेश आने के क्रम में भारतीय रेल ने विभिन्न "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाईं। इन ट्रेनों ने प्रवासी श्रमिकों को देश के कोने–कोने में स्थित विभिन्न शहरों तक पहुंचाने का कार्य संभव बनाया। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से प्रत्येक में अधिकतम 1,200 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई, ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, इन ट्रेनों में बैठने से पहले यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग की गई और सफर के दौरान उन्हें मुफ्त भोजन तथा पानी मुहैया कराया गया।

कोविड–19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 5 मई, 2020 को ऑपरेशन समुद्र सेतु आरंभ किया गया। कुल 55 दिन चले इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना पोत जलाश्व, ऐरावत, शार्दुल तथा मगर ने हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत इन पोतों ने 23,000 कि.मी. से अधिक की समुद्री यात्रा की और कुल 3,992 भारतीय नागरिकों को देश लाने में कामयाबी हासिल की। इन समुद्री यात्राओं के दौरान, समुद्री जहाजों के प्रचालन के वातावरण को ध्यान में रखते हुए कड़े चिकित्सकीय / सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। यह अभियान, भारतीय नौसेना द्वारा विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के साथ सुनियोजित समन्वय से संचालित किया गया।

8 जुलाई, 2020 तक, विश्व भर के 200 से अधिक देशों में कोविड–19 के 11 मिलियन (1 करोड़ 10 लाख) से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इसके कारण 0.5 मिलियन (5 लाख) लोगों की जान जा चुकी है। 10 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार, भारत में कोविड–19 के 2.76 लाख से अधिक सक्रिय मामले सामने आ चुके हैं और इस महामारी के कारण देश में 21,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस महामारी के विरूद्ध देश के इस युद्ध में हमारे समाज के कुछेक वर्गों ने समर्पित भाव से अग्रणी सेवाएं प्रदान की हैं। डाक विभाग, इन कोविड–19 योद्धाओं के सम्मानस्वरूप चार स्मारक डाक–टिकट तथा एक मिनियेचर शीट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक–टिकट / मिनियेचर शीट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका : श्री कमलेश्वर सिंह

विरूपण मोहर : श्रीमती अलका शर्मा

पाठ : इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर।

Salute to COVID-19 WARRIORS

The World Health Organization (WHO) declared a 'Public Health Emergency of International Concern' on 30th January, 2020 owing to an outbreak of pneumonia of unknown etiology since December, 2019. Thereafter, the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) announced "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" as the name of the new virus on 11th February, 2020. This name was chosen because the virus is genetically related to the coronavirus responsible for the SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) outbreak of 2003. WHO announced "COVID-19" as the name of this new disease on 11th February, 2020, following guidelines previously developed with the World Organization for Animal Health (OIE) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Subsequently, WHO declared COVID-19 outbreak as a pandemic (a pandemic is the worldwide spread of a new disease) on 11th March, 2020 and reiterated the call for countries to take immediate action and scale up response to detect, treat and reduce transmission to save people's lives. Hon'ble Prime Minister of India announced a total lockdown in the country effective from midnight on 25th March, 2020 which was later extended till 31st May, 2020 to contain the spread of COVID-19. Government of India has been taking all necessary steps to ensure that India is prepared well to face the challenge and threat posed by the growing pandemic of COVID-19.

COVID-19 warriors, viz. doctors, nurses and health professionals, Police, sanitation workers, Post office and Bank employees and other Government officials involved in providing essential services are leading from the front in serving the people during these trying times.

Health professionals including doctors and nurses are at the front line of the COVID-19 outbreak response and engaged in a gamut of activities ranging from prevention and diagnosis to treatment and supportive care. They are exposed to hazards that put them at the risk of infection. Hazards include pathogen exposure, long working hours, psychological distress, fatigue and occupational burnout. However, battling all odds, health professionals across India have been rendering stellar service in the battle against COVID-19. Union Government has created an online data pool on https://covidwarriors.gov.in of (among others) doctors, nurses and other health care professionals. As part of this online data pool, more than 11 Lakh doctors and 17 Lakh nurses across India have been listed for use by the ground level administration at state, district or municipal levels in the fight against COVID-19.

Police and law enforcement officials play a crucial role in contributing to the effort to control the spread of COVID-19 disease by enforcing social distancing and the strict implementation of the lockdown, promoting safer communities and fighting criminals who take advantage of the outbreak. They are guarding containment zones, enforcing the lockdown and home quarantines and carrying out high-risk evacuations.

An estimated five million sanitation workers in the country put their lives at risk every day and play a critical role in preventing the spread of COVID-19 by ensuring our streets, parks, sewers, septic tanks, communities, public toilets and public spaces are kept clean and hygienic.

Recognizing the key services offered by Post offices and banks, they have been exempted from lockdown restrictions in view of COVID-19. Banks have been operating Mobile ATMs and offering services such as cash deposit and withdrawal, cheque clearances, remittances and government transactions besides offering schemes such as additional liquidity facility for MSME borrowers and other segments including agriculture and self-help groups. Department of Posts operates the world's largest postal service and relying upon its robust and extensive network, has been delivering everything from lifesaving drugs to Covid-19 test kits, to N95 masks, ventilators and other medical equipment. Further, as on 8th July, 2020 officials of Department of Posts facilitated more than 13 crore transactions worth Rs. 2.59 Lakh crore in Postal Savings Bank accounts, 5.36 crore transactions worth more than Rs. 13,000 crore via India Post Payments Bank and 1.63 crore Aadhar Enabled Payments System (AEPS) transactions worth Rs. 3,249 crore.

The Vande Bharat Mission that aims at bringing home Indians stranded in many countries due to COVID-19 pandemic has come as a much needed relief to the Indians abroad and to their near and dear ones at home. The Mission began on 7th May, 2020 with two flights landing in Kochi and Kozhikode from Abu Dhabi and Dubai. Subsequent to the Ministry of Home Affairs order regarding movement of migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons stranded at different places by special trains, Indian Railways operated several "Shramik Special" trains. These trains ferried migrants to cities across the length and breadth of the country. In these Shramik Special Trains, maximum 1,200 passengers were accommodated so as to observe social distancing. Further, proper screening of passengers was ensured before boarding the train and during the journey, passengers were given free meals and water.

Operation Samudra Setu was launched on 5th May, 2020 as part of the national effort to repatriate Indian citizens from overseas during the COVID-19 pandemic. Indian Naval Ships Jalashwa, Airavat, Shardul and Magar participated in this operation which lasted over 55 days and involved traversing more than 23,000 kilometers by sea successfully bringing 3,992 Indian citizens back to their homeland. Rigorous medical/ safety protocols, unique to the operating environment of ships, were implemented. This operation was undertaken by the Indian Navy in close coordination with Ministry of External Affairs, Home Affairs, health and various other agencies of the Government of India and State Governments.

As of 8th July, 2020, more than 11 million cases of Covid-19 have been detected in more than 200 countries and more than 0.5 million people have lost their lives. As of 10th July, 2020 there are more than 2.76 lakh active COVID-19 cases in India and the COVID-19 pandemic has claimed more than 21 thousand lives in India. There are sections of our society that are rendering yeoman's service in the country's fight against COVID-19. Department of Posts is pleased to release a set of four Commemorative Postage Stamps and a Miniature Sheet to pay a tribute to these COVID-19 Warriors.

Credits:

Stamps / Miniature Sheet / FDC / Brochure	: Shri Kamleshwar Singh
Cancellation Cachet	: Smt Alka Sharma
Text	: Based on information available on internet